तस्वीर में नज़र आ रहा यह प्राचीन पगोडा असल में कोरिया का विख्यात डोरीसा मंदिर है, जिसे कोरिया में बौद्ध मत का जन्मदाता माना जाता है। पहाड़ी पर बने इस मंदिर से खूबसूरत घाटियों और नाकदोंग नदी का मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। यहां से थोड़ी दूर पर गूमी शहर भी है उसका भी खूबसूरत दृश्य यहां से देखा जा सकता है। किंवदंती है कि बौद्ध भिक्षुक अदो ह्वासांग (अदो मतलब नाटा) सन् 418 ईस्वी में यहां आया था। यहां भिक्षुक अदो का मंदिर भी है भक्त गण उसके अगर बत्ती जलाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। यह पांच मंजिला देश की सबसे प्राचीनतम व अनूठी इमारतों में से एक है। इसके निर्माण की सटीक तिथि ज्ञात नहीं है पर यह संभवतया गोरयेओ काल (918 ईस्वी से 1392 ईस्वी) में बना था। पत्थर से बनी प्राचीन सीढ़िया सीधे मंदिर के द्वार तक जाती हैं। पगोडा तक जाने के रास्ते में वह जगह भी है जहां भिक्षुक अदो ध्यान लगाते थे। यहां साल भर पीच और प्लम के वृक्षों पर फूल खिले रहते हैं। यहां कोरिया का सर्वाधिक विख्यात राष्ट्रीय खजाना है जो असल में एक षटकोणीय समाधि है, जिसमें बुद्ध शाक्य मुनि की राख रखी हुई है।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ी, पर बढ़त शुक्रवार के मुकाबले कम रही

राज्य में शुक्रवार को 644 मामले बढ़ने के साथ ही 3300 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि गुरूवार को 773 मामले बढ़ने के बाद 2656 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 7 जनवरी । प्रदेश में शुक्रवार को करोना संक्रमण के नए मामलों में और वृद्धि होने के बाद 33 सौ नए संक्रमित मिले हैं। हालाकि यह बढ़ोत्तरी गुरूवार के मुकाबले में कुछ कम रही है। इधर पिछले चौबीस घंटों में सर्वाधिक 1527 नए रोगी राजधानी जयपुर में सामने आए हैं। इस बीच करोना से जयपुर और करौली में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 10 हजार के पार हो गए हैं।

प्रदेश में करोना संक्रमण का दायरा 32 जिलों तक पहुंच गया है। अब केवल जालोर ही एक मात्र ऐसा जिला है जहां फिलहाल न कोई नया संक्रमित है और न ही कोई एक्टिव केस मौजूद है। राज्य में शुक्रवार को गुरूवार के मुकाबले 644 और मामले बढ़ने के साथ ही 3300 नए संक्रमित मिले हैं। जबकि गुरूवार को 773 मामले बढ़ने के बाद 2656 रोगी पाए गए थे।

- **पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा 1527 नए संक्रमित जयपुर में और 440 मरीज जोधपुर में मिले हैं।**
- **राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 5.72 फीसदी और स्वस्थ होने की दर घटकर 98 प्रतिशत हो गई है।**
- **प्रदेश में शुक्रवार को करोना से दो लोगों की मौत होने के साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 10 हजार के पार हो गए हैं।**

इधर जयपुर जिले में लगातार काफी संख्या में करोना के नये मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी में 1527 नये संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 440, अलवर में 219, उदयपुर में 189, बीकानेर में 187, अजमेर में 103, कोटा में 100, भीलवाड़ा में 96, चित्तैड़गढ़ में 85, भरतपुर में 57, सवाईमाधोपुर में 40, प्रतापगढ़ में 32, बाड़मेर में 30, नागौर में 26, डूंगरपुर में 24, राजसमंद में 20, बांसवाड़ा व टोंक में 18-18, गंगानगर में 16, सिरोही में 15, बूंदी में 10, झालावाड़ में 9, चूरू में 8, धौलपुर में 7, हनुमानगढ़ में 6, जैसलमेर व दौसा में 5-5, झुंझुनूं में 4, करौली में 2 तथा सीकर और पाली में 1-1 नया संक्रमित मिला है। राज्य में आज केवल बारां और जालोर जिले में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया।

इधर, केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी करोना संक्रमित हो गए है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि करोना के लक्षण महसूस होने पर जांच कराई, जो पॉज़िटिव आई है। जिस पर खुद को आइसोलेट कर लिया है।

राज्य में शुक्रवार को 279 मरीज और ठीक होने के साथ ही अब तक इस बीमारी से 9 लाख 47 हजार 153 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में नए संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते जहां रिकवरी रेट घटकर 98 फीसदी पर आ गई है। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 5.72 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

उधर प्रदेश में लगातार रिकवरी कम होने व नए मामले बढ़ने से एक्टिव केस बढ़कर 10 हजार 287 हो गए हैं। इनमे सर्वाधिक 5776 मामले जयपुर में हैं। इसके अलावा जोधपुर में 1278, अलवर में 534, अजमेर में 374, बीकानेर में 330, उदयपुर में 328, कोटा में 308, भीलवाड़ा में 206, भरतपुर में 202, चित्तौड़गढ़ में 197 और प्रतापगढ़ में 100 तथा अन्य 21 जिलों में इससे कम मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को करोना से जयपुर और करौली में 1-1 संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब तक इस बीमारी से 8969 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

शुक्रवार को जैश के तीन और आतंकी मारे गये

श्रीनगर, 7 जनवरी (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच गुरुवार रातभर चली मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

- **बीते छह दिनों में यह पांचवीं मुठभेड़ है और अभी तक कुल 11 आतंकवादी मारे जा चुके हैं।**

गौरतलब है कि यह इस साल की पांचवीं मुठभेड़ है और अभी तक कुल 11 आतंकवादी मारे जा चुके हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर के जोवला चदूरा इलाके में कल शाम आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर संयुक्त बलों ने घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया।

नीट पी.जी. काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली

ई.डब्ल्यु.एस. को 10 फीसदी एवं ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी

नई दिल्ली, 7 जनवरी (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यु.एस.) को 10 फीसदी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-2021 (नीट-पीजी) की काउंसलिंग की अनुमति दे दी।

- **ई.डब्ल्यु.एस. उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये की प्रति वर्ष की आय का मानदण्ड लागू रहेगा। मतलब नीट पी.जी. के लिए आठ लाख अधिकतम आय सीमा होगी।**

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने अपने आदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखा, लेकिन कहा कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये प्रति वर्ष की आय मानदंड लंबित याचिकाओं के अंतिम परिणाम के दायरे में होगा।

शीर्ष अदालत की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि उसने इस वर्ष के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय मानदंड को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय अजय भूषण पांडे कमेटी की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं और आरक्षण का समर्थन कर रही केंद्र सरकार का पक्ष विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश के साथ ही नीट-पीजी-2021 परिणाम के आधार पर नामांकन के लिए शीघ्र काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बाधाएं दूर हो गई लगती हैं।

राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटे की सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का मापदंड तय करने को लेकर चल रहे विवाद के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया रुकी हुई थी।

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार की आठ लाख रुपए तक की वार्षिक आय की सीमा तय की है। पीठ इस मापदंड तय करने का तौर तरीका जानना चाहता था। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2021 को एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी।

महाराष्ट्र में करोना के नये मामले 40 हजार के पार

मुंबई, 7 जनवरी (वार्ता)। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के नये मामलों की संख्या 40 हजार पार कर गयी तथा 20 मरीजों की मौत दर्ज की गयी है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 40,925 नये संक्रमित सामने आये हैं।

- **महाराष्ट्र में 20 लोगों की करोना से मौत हुई, वर्तमान में महाराष्ट्र में 1,41,492 मामले सक्रिय हैं।**

नये मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 68,34,222 हो गयी तथा मृतकों का आंकड़ा 1,41,614 हो गया। इसी अवधि में 14,256 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 65,47,410 हो गयी।

डब्ल्यु.एच.ओ. के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुशलतापूर्वक लगाने की तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके।

इसमें एक आशा की किरण यह है कि वर्तमान में ट्रायल मोड में चल रहीं कुछ वैक्सीन्स की अविष्कारक कम्पनियां अपने पेटेन्ट त्यागने और अपने लायसैंस व तकनीकी जानकारियां साझा करने पर पहले ही सहमत हो चुकी हैं। उनका यह कदम "जोनस सल्क" की भांति है, जिन्होंने अपनी पोलियो वैक्सीन का पेटेन्ट नहीं कराया, और ऐसा करके इस बीमारी से करोड़ों बच्चों को बचाया था।

समाचार एजेंसी ए.एफ.सी. की रिपोर्ट कहती है कि टेड्रोस ने गुरूवार को दिए वर्ष 2022 के अपने पहले संबोधन का उपयोग वैक्सीन के गत वर्ष उपलब्ध डोज़ेज़ को हथियाकर बैठे समृद्ध देशों की आलोचना करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि उनकी इस प्रवृत्ति ने इस वायरस के अन्य वेरिएन्ट्स के पनपने के लिए एक माकूल प्रजनन स्थल निर्मित कर दिया है।

उन्होंने दुनिया के देशों से अनुरोध किया कि वे कोविड-19 की "मौतों और विनाश" को खत्म करने के लिए वर्ष 2022 में अधिक निष्पक्षता के साथ वैक्सीन डोज़ लगाएं।

टेड्रोस ने पहले इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक देश सितम्बर 2021 तक अपनी आबादी के 10 प्रतिशत और दिसम्बर-2021 तक 40 प्रतिशत हिस्से को वैक्सीन लगाए।

लेकिन वर्ष 2021 की समाप्ति तक के इस तय लक्ष्य को डब्ल्यू.एच.ओ. के 194 सदस्य राष्ट्र पूरा नहीं कर सके। वास्तव में इनमें से 36 देश तो ऐसे थे जो वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते अपनी आबादी के 10 प्रतिशत हिस्से को भी वैक्सीन नहीं लगा सके। टेड्रोस चाहते हैं कि वर्ष 2022 के मध्य तक प्रत्येक देश अपनी 70 प्रतिशत आबादी को वैक्सीन लगाए।

इस बीच, डब्ल्यू.एच.ओ. की कोविड-19 टैक्नीकल टीम की प्रमुख मारिया वान कर्खोव ने कहा कि इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि इस वैश्विक महामारी की समाप्ति से पूर्व ओमक्रॉन ही अंतिम चिंताजनक वेरिएन्ट होगा। अधिक संक्रामक प्रकृति के ओमक्रॉन वेरिएन्ट को लेकर वान कर्खोव ने लोगों से अनुरोध किया कि वे उन्हीं एहतियातों का और कड़ाई से पालन करें जिन्हें वे इस वायरस से स्वयं को बचाने के लिए बरतते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि "हम जिन पहलुओं को बेहतर, विस्तृत और अधिक उद्देश्यपटकता के साथ समझाते रहे हैं। उन पर हर संभव तरीके से अमल करें, हम चाहते हैं कि लोग इसका डटकर मुकाबला करें।"

करोना वायरस से निबटने के साधन जुटाने वाले डब्ल्यू.एच.ओ. के प्रतिनिधि ब्रूस एल्वर्ड ने इस वर्ष में एक आशावाद जताते हुए कहा कि वर्ष 2022 में किसी वैश्विक महामारी के आगे घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है।

किन्तु डब्ल्यू.एच.ओ. के आयातकालीन विभाग के निदेशक माइकल रेयान ने कहा कि "वैक्सिनेशन के समान स्तर के बिना इस वर्ष 2022 के समापन तक यहां बैठे वार्तालाप करते रहेंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ी त्रासदी होगी।"

विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों को सात दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा

केन्द्र सरकार ने विमान यात्राओं के मामले में नये दिशा निर्देश जारी किये जो कि 11 जनवरी से प्रभावी होंगे

नई दिल्ली, 7 जनवरी (वार्ता)। करोना महामारी के मद्देनजर ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, चीन और इजराइल आदि जोखिम वाले राष्ट्रों से भारत आने वाले सभी यात्रियों का कोविड परीक्षण होगा और सभी देशों से आयें लोगों को अनिवार्य रूप से सात दिन तक क्वारंटीन में जाना होगा तथा आठवें दिन कोविड परीक्षण कराना होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किये। ये दिशा निर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे।

संशोधित दिशा निर्देश में कहा गया है कि भारत आने वाले सभी यात्रियों को सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट तथा स्व घोषणा पत्र डालना होगा। जोखिम वाले राष्ट्रों से भारत आने पर सभी यात्रियों का उनके खर्चे पर कोविड परीक्षण किया जायेगा और कोविड पाजिटिव आने पर कोविड मानकों के अनुरूप इलाज होगा। अन्य राष्ट्रों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और कोविड लक्षण दिखने पर उनका कोविड परीक्षण होगा। सभी यात्रियों में से दो प्रतिशत का रैंडम कोविड परीक्षण होगा। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आवश्यक नहीं है लेकिन कोविड लक्षण दिखने पर उचित प्रक्रिया अपनायी जायेगी। दिशा निर्देश में कहा गया कि विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सात दिन के लिए क्वारंटीन में जाना होगा और आठवें कोविड परीक्षण कराना होगा। ये दिशा निर्देश हवाई अड्डे, बंदरगाह और स्थल मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होंगे। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते जोखिम वाले राष्ट्रों की सूची में उन देशों को रखा है, जहां संक्रमण एक निर्धारित स्तर से ज्यादा है।

किसान ने मंच पर भाजपा विधायक को थप्पड़ जड़ा

उन्नाव, 7 जनवरी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भाजपा के विधायक को एक किसान ने भरी सभा के बीच थप्पड़ जड़ दिया। उन्नाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ जड़ने वाले बुजुर्ग किसान को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया और मंच से नीचे उतारा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग किसान मंच पर आता है। उसके हाथ में एक लाठी है। वह मंच पर बैठे भाजपा विधायक के नजदीक आता है और एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और किसान को पकड़ लेते हैं। किसान ने बीकेयू की टोपी पहन रखी थी। विधायक के समर्थक किसान को घेरने लगे थे लेकिन पंकज गुप्ता ने किसी को भी किसान पर हाथ न उठाने को कहा।

'प्र.मंत्री ने कोलकाता के कैंसर संस्थान का दोबारा उद्घाटन किया'

प्र.मंत्री के कार्यक्रम के दौरान ही ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुये कहा, इस संस्थान का राज्य सरकार पहले ही उद्घाटन कर चुकी है

कोलकाता, 7 जनवरी (वार्ता)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में जिस कैंसर संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया, उसका उद्घाटन राज्य सरकार ने पहले ही कर दिया था और अभी उसे कोविड केंद्र के रूप में उपयोग किया जा रहा था।

प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिती में कोलकाता में चित्तरंजन कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया।

ममता बनर्जी के शुरूआती संबोधन में उनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट नजर आ रहा था और इसलिए वह अपना उपनाम भूल गयी। उन्होंने इस कार्यक्रम के समायोजक को याद दिलाया।

उन्होंने कहा,आप मेरा उपनाम भी भूल गए है...या शायद घबरा गए हैं। बनर्जी ने मोदी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री वर्चुअली इस परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे दो बार फोन किया। इसलिए मैंने सोचा कि यह कोलकाता का कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री ने रुचि ली है।"

उन्होंने कहा,जानकारी के लिए मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हमने इसका उद्घाटन पहले ही कर दिया है। हमने यह कैसे किया...जब कोविड फैल रहा था, तब हमें कोविड केंद्रों की जरूरत थी। मैं वहां गयी, मैंने देखा कि यह राज्य सरकार के अंतर्गत है इसलिए हमने इसे कोविड केंद्र बना दिया और यह काफी उपयोगी साबित हुआ था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस परिसर के लिए 25 प्रतिशत धन मुहैया करायी है और हर साल 71 करोड़ रुपये का खर्च वहन करने सहित राज्य ने इस परियोजना के लिए 11 एकड़ जमीन दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक मेडिकल सीटों और अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भी जरूरत है।

'पंजाब में राष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर दिया। हमने देश के लिये कई युद्ध लड़े हैं तथा हम में से अनेकानेक लोग अपने कर्तव्य को निभाते हुये शहीद हो गये हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रधानमंत्री की खातिर गोली खाने वाला पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ?" चन्नी ने कहा कि पंजाब में न तो कोई पत्थर फैंके गये, न कोई गोली चली और न प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नारे ही लगे। उन्होंने मोदी के इस बयान कि "मैं ज़िन्दा बच गया", पर आश्चर्य व्यक्त किया है। राज्य पी.सी.सी. प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधी चूक के आरोप को एक प्रहसन बताया है तथा कहा है कि प्रधानमंत्री और भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के जीवन को लेकर व्यक्त की गई फर्जी चिन्ता का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में राजनैतिक लाभ प्राप्त करना है। चूँकि भाजपा पंजाब में बहुत कम चुनावी संभावनाएँ देख रही है, इसलिये भगवा पार्टी को यह उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे का ढ़ोल पीटकर, मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री हुसैनवाला जा रहे थे, जहाँ उन्हें राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर एक सभा को संबोधित करना था। इसलिये, पंजाब की घटना, पार्टी के राष्ट्रवाद के प्रचार के अनुकूल नहीं बैठती।

भाजपा की रणनीति "कांग्रेस, पाकिस्तान और खालिस्तान के बीच की साँठ-गाँठ" के ईदगिर्द पहले से ही चल रही है। केन्द्र सरकार तथा पंजाब सरकार दोनों ने ही इस घटना की जाँच शुरू कर दी है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जायें। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया है कि वे इस सारे रिकॉर्ड को "सुरक्षित अभिरक्षा" (सेफ कस्टडी) में रखें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पंजाब पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप तथा केन्द्र एवं राज्य की अन्य एजेंसियाँ उनका सहयोग करेंगी तथा उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेंगी।

- **विपक्ष ने, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश भी शामिल हैं, भी प्र.मंत्री की जान को खतरे वाली बात पर भाजपा का भारी मखौल उड़ाया।**

हाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की जेलों में करीब 55 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने प्र.मंत्री सुरक्षा में चूक के मामले में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य सरकार से भी कहा है कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा से संबंधित सुरक्षा उपायों में हुई कथित चूक की जाँच के लिये उनके द्वारा गठित कमेटियों द्वारा आगे की जाने वाली किसी भी कार्यवाही को 10 जनवरी को होने वाली सुनवाई तक रोक दिया जाये। ये निर्देश दिल्ली के अधिकारों से जुड़ी संस्था "लॉयर्स वॉइस" द्वारा दायर एक याचिका के फलस्वरूप जारी किये गये।

5 जनवरी को प्रधानमंत्री का काफिला उस समय एक फ्लाई ओवर पर 15-20 मिनट तक रुका रहा था जब वे भटिण्डा से पंजाब के फिरोज़पुर स्थिति हुसैनवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जा रहे थे।

इसके बाद उनका काफिल भटिण्डा हवाई अड्डे पर लौट आया था। सुरक्षा में हुई असाधारण चूक उन विरोध प्रदर्शन करने वालों के कारण हुई थी, जिन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी थी।

इस बीच, प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई इस कथित सुरक्षा-चूक के बाद, गृह मंत्रालय ने भटिण्डा के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक को "कारण बताओ" नोटिस जारी कर दिया है, जिसका जवाब एक दिन में ही देने के लिये कहा गया है।

काफी सख्त भाषा में लिखे गये इस पत्र, जिसकी एक प्रति "द ट्रिब्यून" के पास है, में केन्द्र सरकार की उप सचिव अर्चना वर्मा ने कहा है कि चूँकि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा-संबंधी गंभीर चूक हुई थी, इसलिये भटिण्डा के एस.एस.पी. को निर्देश दिया जाता है कि वे स्पष्टीकरण दें कि ऑल इंडिया सर्विसेज़ (डिसिजियन एंड अपील), रूल्स 1969 के तहत चूक एवं खामी के कृत्य के फलस्वरूप उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित, कानूनी कार्यवाही क्यों न की जाये।

पत्र कहता है: "आपका जवाब इस मंत्रालय में 8 जनवरी को सायं 5 बजे या उससे पहले पहुँच जाना चाहिये, ऐसा न होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम फिरोज़पुर में हुई कथित सुरक्षा-चूक की जाँच कर ही रही है। इस टीम ने उस फ्लाई ओवर का निरीक्षण किया, जहाँ किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री का काफिला रूक गया था। इस विरोध से बाध्य होकर काफिले को आगे की सड़क-यात्रा निरस्त कर दी गई तथा उन्हें नई दिल्ली लौटना पड़ा।

इसी प्रकार की तत्परता दिखाते हुये, पंजाब सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में, एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है तथा दो सदस्यों का एक पैनल भी गठित कर दिया गया है। ,

मुख्य सचिव अनिरूद्ध तिवारी ने उस सुरक्षा-चूक के संबंध में एक रिपोर्ट केन्द्र को सौंप दी है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा रूक गई थी। उन्होंने केन्द्र को सूचित किया है कि इस घटना को लेकर एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है तथा इन खामियों की जाँच के लिये राज्य सरकार ने दो सदस्यों का एक पैनल भी गठित कर दिया है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि समझा जाता है कि तिवारी ने बुधवार को घटी घटनाओं के क्रमवार सिलसिले से संबंधित विस्तृत विवरण भी साझा किया है।

पंजाब सरकार ने सुरक्षा-चूक की जाँच के लिये दो सदस्यों का पैनल गठित करने की घोषणा गुरूवार को कर दी थी। पैनल से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट तीन दिन में दे दे।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिये थे कि वह यह रिपोर्ट तुरन्त भेजे। मंत्रालय ने कहा था कि राज्य सरकार ने आवश्यक तैनाती सुनिश्चित नहीं की थी, जबकि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था में ऐसी चूक एवं लापरवाही पूरी तरह अस्वीकार्य है तथा इसकी जवाबदेही तय की जायेगी।

इस घटना के फलस्वरूप एक बड़ा राजनैतिक विवाद शुरू हो गया है। भाजपा आरोप लगा रही है कि पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को "शारीरिक क्षति पहुँचाने की कोशिश की।" अन्य दलों ने भी कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा हैं।

पंजाब यात्रा के दौरान मोदी की सुरक्षा के साथ समझौता किये जाने के भाजपा के आरोप की हवा निकालने की कोशिश में पी.सी.सी. अध्यक्ष सिद्धू ने आज कहा कि भगवा दल ने सुरक्षा-चूक का यह नाटक उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया है।

सिद्धू ने कहा कि केन्द्र "गंदी राजनीति" खेल रहा है तथा प्रधानमंत्री पार्टी की इस असफलता को छिपाना चाहते थे कि फिरोज़पुर की सभा में पर्याप्त भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकी।

सिद्धू ने कहा कि भाजपा उन किसानों की सुरक्षा को लेकर तो चिन्तित नहीं थी जो एक साल से ज्यादा समय तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे थे तथा उस आंदोलन के दौरान ही 700 किसानों की मृत्यु तक हो गई थी।

सिद्धू ने कहा, "अब वे अपने लिये सुरक्षा संबंधी खतरे का ड्रामा कर रहे हैं।"

पी.सी.सी. चीफ ने कहा कि चुनावों को ध्यान में रखते हुये, भाजपा ने यह मुद्दा पैदा कर लिया है ताकि लोगों का ध्यान पंजाब के मतदाताओं के मुद्दों से हटाया जा सके।

सिद्धू ने कहा, "भाजपा को इस प्रकार की राजनीति रोक देनी चाहिये। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जैसे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की माँग करने वाले लोग तो आपके तोते हैं।" उन्होंने पूछा, "क्या उन्होंने राज्य का कोई और मुद्दा उठाया है?"

- **पंजाब पी.सी.सी. के अध्यक्ष सिद्धू ने कहा, दिल्ली की सीमा पर आंदोलनकारियों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की तथा 700 किसान मरे, अब अपनी सुरक्षा के बारे में भारी "ड्रामा" कर रहे हैं।**

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा अरावली प्रिन्टर्स, जयपुर रोड, अजमेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908